

कुमाऊं जनसन्देश

www.kumaonjansandesh.com

वर्ष - 7 अंक - 11 हल्लानी(नैनीताल) सोमवार 10 फरवरी 2025 पृष्ठ - 4 मूल्य - 1

शहर की सरकार ने संभाला कार्यभार

हल्लानी में मेयर गजराज सिंह, काशीपुर में मेयर दीपक बाली और रुद्रपुर में मेयर विकास शर्मा समेत पार्षदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

हल्लानी। शहर की सरकार ने शुक्रवार को जिम्मेदारी संभाल ली है। रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की उपस्थिति में मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने 60 पार्षदों के साथ शपथ ली। इस मौके पर मेयर गजराज बिष्ट जनता का आभार जताते हुए कहा कि संकल्प पत्र में हमने जो वादे किये हैं, उसे अक्षरशः पूरा किया जायेगा। जनता के विश्वास व उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छुयेंगे।

रामलीला मैदान में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नवनिर्वाचित मेयर गजराज बिष्ट को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद मेयर बिष्ट ने 60 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया। जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, नैनीताल सरिता आर्य समेत तमाम पाटह पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को बधाई दी। इस दौरान मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि वे जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। पिछले कार्यकाल के कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ही शहर के विकास के लिए नए कार्य किए जाएंगे। हल्लानी शहर का चहुमुखी विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। समारोह में भाजपा



जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, मंडी परिषद अध्यक्ष डा. अनिल कपूर डब्लू, आनंद सिंह दरमवाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी चन्दन बिष्ट, तरुण बंसल, प्रदीप बिष्ट, मजहर नईम नवाब, दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट, रंजन बर्गली, दिनेश आर्य, प्रमोद बोरा, अजय राजौर, प्रदीप जनौटी के साथ ही नगर आयुक्त ;चा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, उपजिलाधिकारी पारितोष वर्मा के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इधर, शपथ ग्रहण समारोह के बाद मेयर गजराज बिष्ट ने नगर निगम कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इसके बाद निगम सभागार में पहली बोर्ड बैठक हुई, जिसमें सभी पार्षदों का परिचय हुआ। साथ ही शहर के विकास के एजेंडे पर चर्चा हुई।

काशीपुर। नगर निगम काशीपुर के प्रांगण में आयोजित नवनिर्वाचित नगर निगम बोर्ड शपथ ग्रहण समारोह में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पहुंचकर नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली को पद एवं गोपनीयता की शपथ

दिलाई। इसके बाद मेयर दीपक बाली ने नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी भदौरिया ने नवनिर्वाचित मेयर व पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नये बोर्ड के गठन से काशीपुर शहर विकास की नई उचाईयों को छुएगा ऐसा मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा कि शहर की जो भी समस्याएं हैं वह प्राथमिकता से समाधान हो सकेगा व विकास के कार्य और तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नये बोर्ड के गठन से सभी के सहयोग से शहर साफ, सुथरा, स्वच्छ व सुन्दर बन सकेगा। मेयर दीपक बाली ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर निगम बोर्ड की बैठक कर काशीपुर के विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर सभी कार्य प्राथमिकता से कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों के साथ मिलकर काशीपुर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुन्दर बनाने के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह

चीमा, राजीव अग्रवाल, पूर्व मेयर उषा चौधरी, नगर आयुक्त विविक राय, प्रदेश महामंत्री खिलेन्द्र चौधरी, राम महरोत्रा, मुक्ता सिंह, आशीष गुप्ता, सहित बड़ी संख्या में गणमान्य, जनप्रतिनिधि व जनता मौजूद थी। रुद्रपुर। गांधी पार्क में वैदिक मंत्रोच्चारण व शंख ध्वनि के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नवनिर्वाचित महापौर नगर निगम विकास शर्मा को शपथ ग्रहण समारोह में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद महापौर विकास शर्मा ने नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्या अतिथि सूबे की खेल, युवा कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने सम्बोधित करते हुए महापौर विकास शर्मा व पार्षदों को बधाई दी। उन्होंने कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए नगर निगम रुद्रपुर वासियों को महापौर चुनने के लिए बधाई दी व आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महापौर अपने नाम के अनुरूप रुद्रपुर के सर्वांगीण

विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार रुद्रपुर नगर निगम के विकास हेतु हमेशा महापौर के साथ रहेगी। मंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी पूर्ण सहयोग देंगी। कार्यक्रम में सभी अतिथियों, महापौर व पार्षदों को नगर आयुक्त की टीम द्वारा पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक शिव अरोरा, अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन विनय रूहेला, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्लू, उत्तम दत्ता, जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल, गुंजन सुखीजा, जिला महामंत्री अमित नारंग, पुष्कर काला, अनिल चौहान, दीप कोश्यारी, दीपक मेहरा, सत्यप्रकाश चौहान, नेत्रपाल मौर्य, दिवाकर पाण्डे, सुरेश परिहार, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, राजकुमार ठुकराल, पूर्व मेयर रामपाल सिंह, जसपाल कोली, मनोज मदान, के के दास, विपिन जलहौत्रा, राजेश कालड़ा, राकेश सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, शालिनी बोरा, नरेन्द्र अरोरा, महन्त शिवानन्द महाराज, रमेश वशिष्ठ आदि मौजूद थे।

खिलाड़ी नेशनल रिकार्ड तोड़ने का करें प्रयास

रुद्रपुर। रुद्रपुर के नवनिर्मित बहुउद्देशीय हथल में खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों की हैंडबल प्रतिযোগिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए इस बहुउद्देशीय हथल का निर्माण किया गया है। यहां के भावी खिलाड़ियों के लिए यह बहुत लाभकारी होगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इन राष्ट्रीय खेलों चलते रुद्रपुर को साइकिलिंग वैलोटोम, बहुउद्देशीय हाल और शश्वटगन शूटिंग रेंज के रूप में तीन तोहफे मिले हैं। इन खेल अवस्थापनाओं में प्रैक्टिस करके भविष्य में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। कहा कि

इस हथल में पहली प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों की हो रही है ऐसे में अगर खिलाड़ी कोई नेशनल रिकार्ड तोड़े तो सही मायने में इस बहुउद्देशीय हाल का सबसे अच्छा उद्घाटन यही होगा। इस अवसर पर उत्तरांचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, महासचिव डी.के. सिंह, डायरेक्टर आफ कंपीटशन गुरुचरण सिंह गिल, प्रीतपाल, कोच उत्तराखण्ड हैण्डबाल सुनील पाठक, अध्यक्ष जिला ओलंपिक संघ नागेन्द्र शर्मा, जिला खेल अधिकारी जानकी कार्की, डीओ पीआरडी बीएस रावत, जिला प्रोवशन अधिकारी व्योमा जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी मौजूद रहे।

सीडीओ ने की विकास योजनाओं की समीक्षा

आवास योजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश

रुद्रपुर। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी, मनीष कुमार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनपद में संचालित ग्राम्य विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। जिसमें प्रधानमंत्री जनमन एवं आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामोत्थान योजना द्वरीपत्र, डीडीयू-जीकेवाई, हाउस आफ हिमालय, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना आदि की विकास

खण्डवार वीसी के माध्यम से समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने पीएमएवाईजी में समस्त अपूर्ण 43 आवासों एवं जनमन आवास योजना के आवासों को 15 फरवरी, 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार एवं कार्यपूर्ति दर बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु रोजगार अवसर हेतु सुझाव दिये, साथ ही ग्रोथ सेक्टरों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु भी निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी ने रीप परियोजना में स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद को स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराये जाने हेतु सुदृढ़ मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध

कराने के निर्देश दिये। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी काशीपुर को सेक्टर का निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये। हाउस आफ हिमालय में उत्पादों की सूची बनाये जाने के निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता लाये जाने के निर्देश दिये ताकि ग्राम स्तर के अन्तिम व्यक्ति तक योजना के लाभ पहुंच सके। उन्होंने आजीविका मिशन के कार्यों में तेजी लाये जाने हेतु बलश्रक मिशन मनेजर जसपुर व बाजपुर को कड़ी फटकार लगाते हुये वेतन रोके जाने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये जिला विकास अधिकारी को दिये।

सम्पादकीय...

डिजिटल तकनीक में पिछड़ने का खतरा
बीते दिनों अमेरिकी बाजार धराशायी हो गए, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर देखा गया। शेयर बाजार में इस भारी गिरावट के पीछे एक चीनी स्टार्टअप द्वारा बेहद कम दाम पर विकसित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप डीपसीक रहा। डीपसीक के आगमन से दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में एक ट्रिलियन डॉलर का झटका डालने तक की गिरावट आई। यह सब तब हुआ जब अमेरिका ने चीन को अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और एआइ के क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी देश घोषित कर उस पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं, ताकि वह इस क्षेत्र की तकनीक या तो विकसित न कर सके और यदि करे भी तो अमेरिकी कंपनियों से कहीं पीछे ही रहे। इसके बावजूद डीपसीक को कई कसौटियों पर प्रमुख अमेरिकी एआइ एप चौटजीपीटी जितना ही सक्षम पाया गया। डीपसीक बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसने यह माडल अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले 10 गुना कम लागत पर विकसित किया है। जहां अग्रणी अमेरिकी एआइ कंपनियां अपने चौटबोट को 16000 जीपीयू से युक्त सुपरकंप्यूटरों पर प्रक्षिप्त करती हैं, वहीं डीपसीक ने मात्र 2000 जीपीयू क्षमता के उपयोग से ही सक्षम एआइ टूल तैयार कर दिया। चीन ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने स्वयं के बल पर प्रथम पंक्ति की तकनीक विकसित करने की क्षमता दिखाई।

डीपसीक की आलोचना इसलिए हो रही है कि वह चीन के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, परंतु उसकी तकनीकी क्षमताओं और कम लागत वाले माडल पर कोई सवाल नहीं उठा है। स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम को अमेरिका के लिए जगाने वाली घंटी कहा है। अमेरिका के सरकारी एआइ प्रोजेक्ट स्टारगेट पर काम कर रही कंपनियों जैसे माइक्रोसाफ्ट और ओपन एआइ के अधिकारियों ने डीपसीक की क्षमताओं को खासा प्रभावी माना है। यह समझना आवश्यक है कि डीपसीक जैसे टूल राजनीतिक प्रश्नों का जवाब तलाशने के लिए नहीं, बल्कि जटिल तकनीकी कार्यों के लिए हैं, जिसमें डीपसीक माडल काफी सस्ता और प्रभावी है। ऐसे में लागत घटाने और लाभ बढ़ाने के लिए कंपनियां उसके उपयोग को तरजीह देंगी। हालांकि अमेरिकी सरकार अपनी टेक कंपनियों के दबाव में डीपसीक पर प्रतिबंध लगा रही है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि डीपसीक अमेरिकी यूजर्स का डाटा चुरा सकता है, परंतु ऐसे प्रतिबंधों की सीमाएं हैं। कारण यह है कि तमाम अमेरिकी कंपनियां अपने माल का उत्पादन चीनी कंपनियों से चीन में कराती हैं। ये चीनी कंपनियां डीपसीक का उपयोग करने वाली हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां अपने चीनी उत्पादकों से जो भी डाटा, जिसमें डिजाइन और पेटेंट से जुड़ी जानकारीयां भी होती हैं, वह साझा करेंगी। अंततः सारा डाटा डीपसीक तक पहुंचेगा। यह बहुत हद तक भारत के मामले में भी सच है, क्योंकि तमाम भारतीय कंपनियां भी चीन में उत्पादन कराती हैं। ओपन एआइ या डीपसीक जैसा कुछ बनाने से हम कोसों दूर हैं। हमारी आइटी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का बैकरोम आफिस बनकर ही खुश हैं। हमारे विश्वविद्यालय ऐसी पीएचडी बांटेकर संतुष्ट हैं, जिनमें कोई उल्लेखनीय खोज नहीं होती। ब्रेन-ड्रेन रोकने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमारे उद्योगपति भी किसी क्रांतिकारी तकनीक के आविष्कार के लिए धन उपलब्ध नहीं कराते। रही बात भारतीयों के डाटा चोरी होने की तो वह तो अमेरिका और चीन, दोनों की कंपनियां कर रही हैं। विश्वस्तरीय एआइ टूल बनाना तो दूर, अभी हम स्वदेशी ईमेल और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म तक नहीं बना पाए हैं और पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं। एक्स और मेटा के एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं, जो वे दिखाना चाहते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम ऐसा कुछ करने की बहुत देर से सोचते हैं। जब तक किसी उपयोगी टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, तब तक वह पुरानी हो चुकी होती है। लचर अनुसंधान के चलते हमें स्वयं ही अपने पर विश्वास नहीं है। ऐसे में हम कोई न कोई विदेशी बैसाखी ढूंढने के आदी हो चुके हैं। इसका ताजा उदाहरण भारत आए अमेरिकी कंपनी ओपन एआइ के मुखिया सैम आल्टमैन की ओर से यह कहकर भारत को रिझाने की कोशिश है कि भारत में एआइ को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। इन्होंने आल्टमैन को कुछ समय पहले तक भारत के एआइ टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों पर संदेह था। अब उनके सुर इसलिए बदले हैं, क्योंकि डीपसीक से मिल रही कड़ी टक्कर के चलते कई देशों का बाजार उनके हाथ से निकल सकता है। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि जब आल्टमैन भारत में थे, तभी यह खबर भी आई कि सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी चौटजीपीटी और डीपसीक जैसे टूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। ऐसी चेतावनी देने के साथ हमें अपनी क्षमताओं को भी परखना होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। हाल में भारत में भारतीय सेना के लिए बनाए गए ड्रोन का कुछ महीने पहले चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हैक कर अपने नियंत्रण में लेने संबंधी खबर इसी चिंता को बयान करती है। यूं तो ये ड्रोन भारत में बनाए गए थे, लेकिन जब चीनी सेना द्वारा इसे हैक कर लिया गया तो पता चला कि इसे सिर्फ भारत में असंबल किया गया था और तमाम कलपुर्जे चीनी थे। यदि यह सब सच है तो गंभीर चिंता की बात है। ऐसे में समय रहते कमियों को दूर करने के कदम उठाने ही होंगे।

दून के नव निर्वाचित मेयर और पार्षदों ने ली पद की शपथ



आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने दिलाई शपथ, ऋषिकेश में डीएम बंसल ने दिलाई मेयर-पार्षदों को शपथ

देहरादून। आपदा उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल सहित सभी 100 पार्षदगणों ने शुक्रवार को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नगर निगम देहरादून के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रशासक/आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने नव निर्वाचित मेयर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद मेयर ने सभी नव निर्वाचित

पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, विधायक विनोद चमोली, सविता कपूर, खजानदास, उमेश शर्मा काऊ, बृजभूषण गैरोला व दुर्गेश्वर लाल, पूर्व केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व महापौर सुनील उनियाल गामा, जिलाधिकारी सविन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम नमामि बंसल, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और लोग मौजूद थे।

देहरादून/ऋषिकेश। तीर्थ नगरी ऋषिकेश नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान सहित सभी 40 पार्षदगणों ने शुक्रवार को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। श्री भरत मंदिर इंटर कालेज ऋषिकेश में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रशासक/जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नगर आयुक्त शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी स्मृता परमार, अन्य अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नगर निगम की जनता मौजूद थी।

श्रिल ब्लेजर ने केदारकांठ ट्रेकिंग पर पहुंचाएं सबसे अधिक पर्यटक

देहरादून। वड़ोदरा की श्रिल ब्लेजर कंपनी ने वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 12,500 फीट ऊंचाई पर स्थित केदारकांठ ट्रेकिंग स्थल पर सबसे अधिक लोगों को ट्रेकिंग पर ले जाकर अनूठी उपलब्धि हासिल की है।

इस संबंध में श्रिल ब्लेजर के संस्थापक धैवत पंड्या ने बताया कि 44 किलोमीटर का ट्रेकिंग रूट उत्तराखंड के सांकरी गांव से शुरू होता है। वहां से, ट्रेकर जुड़ाका तालाब के रास्ते बेस कैम्प तक पहुंचता है। वहां से, ट्रेकर केदारकांठ शिखर तक पहुंचने के लिए तीन फीट बर्फ को पार करते हुए

रवाना हुए। यात्रा के दौरान, ट्रेकर रोहिणी, त्रिशूल, नीलकंठ और भारत-तिब्बत सीमा पर पर्वत श्रृंखलाओं को भी देखते हैं। ट्रेक के दौरान ट्रेकर कैम्प फायर करते हैं और साथ ही मोबाइल फोन से दूर रहकर प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। इस शिविर में जाने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, यही कारण है कि यह शिविर इतना महत्वपूर्ण है। पिछले पांच वर्षों से श्रिल ब्लेजर कंपनी को गुजरात पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर ट्रेवल कंपनी का पुरस्कार दिया जा रहा है।

साइबर सुरक्षा से बचाव की दी जानकारी

केंद्रीय विद्यालय में शिविर लगाकर छात्रों को किया गया जागरूक

देहरादून। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून सीमा डूंगराकोटी द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय नं. -1, सालावाला, देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, पोक्सो, अधिनियम, मोटर वाहन एक्ट, नालसा टोल प्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली निरूशुल्क विधिक सेवाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा समस्त छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। जिसमें उन्होंने छात्र-छात्राओं को आह्वाहन किया कि

अगर कोई किशोर वाहन चलाता है और सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है तो कानून के तहत इसकी सजा उसके अभिभावकों को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चलाने हेतु वाहन चालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।

वैध लाइसेंस बनने के बाद ही वाहन चलाने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य मयंक शर्मा, अध्यापकगणों के साथ-साथ लगभग 350 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरु

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक विनोद चन्द्र पनेरु द्वारा भीड़पानी-ओखलकांडा प्रिंटिंग प्रेस(मोती सिंह), भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित तथा हरिपुर लालमणि पो.आ- देवलचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखंड) से प्रकाशित। मो. 9410354318 Email:-vinodpaneru123@gmail.com

अमेरिका से भारतीयों को खदेड़ने पर कांग्रेस ने केन्द्र को कोसा



कांग्रेस भवन में ताजा हालात पर गोष्ठी का आयोजन

देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विरेन्द्र पोखरियाल की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अमेरिका द्वारा भारत के लगभग 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भारत भेजे जाने के विरोध के खिलाफ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें अमेरिका और मोदी सरकार की कड़ी अलोचना की गई। इस अवसर पर पोखरियाल ने मोदी सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार जानती थी कि 5 फरवरी को 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी और जंजीरें पहनाकर अमानवीय तरीके से अमेरिका से भारत भेजा जाएगा? क्या मोदी सरकार जानती है कि अमेरिका में ऐसे 7.25 लाख भारतीय हैं जिन्हें इसी तरह से निकालने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि मोदी जी की चुप्पी से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उन्हें देश के अपमान की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि ये भारतीय नागरिकों के साथ उग्रवादियों का जैसा व्यवहार है या माननीय व्यवहार है? ऐसे कितने भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका ने इसी अमानवीय तरीके से डिट्रेशन सेन्टर में बन्द किया है? क्या डिट्रेशन सेन्टर में बन्द भारतीयों को काउंसलर एक्सेस दिया गया है? 100 करोड़ रुपया खर्च कर 'नमस्ते ट्रंप' करने वाली मोदी सरकार लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पाई? अमेरिका से वापस आने वाले लोगों के लिए सरकार क्या करने वाली

है? मोदी सरकार ने कोलंबिया की तरह अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा क्यों नहीं की? मोदी सरकार को इन प्रश्नों का उत्तर देश की जनता को देना चाहिए। संजय शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से भारत के नागरिकों को अमेरिका द्वारा अपने विमान से भारत भेजा गया वह देश को शर्मसार करने वाला है।

पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे वह अब मौन क्यों है? जिस तरह से भारतीय नागरिकों को अमानवीय हालत में हथकड़ी लगाकर और पैरों में जंजीर से बांधकर जानवरों की तरह भारत भेजा गया वह अमेरिका की दादागिरी है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि जिस तरह हमारे देश के नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों को हथकड़ी और जंजीरों में भेजा गया। केन्द्र सरकार ने अमेरिका को इसका माकूल जवाब देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेन्द्र शाह ने केन्द्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा द्वारा मोदी को महिमामंडित किया, वह केवल और केवल देश को ठगने और छलने का काम किया गया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संग्राम सिंह पुण्डरी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि इतना होने के बावजूद भी अभी तक मोदी ने अमेरिका पर कोई भी बयान नहीं दिया है जो कि हतप्रभ करने का वाला है।

प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी ने कहा कि भाजपा देश की जनता को हिन्दू मुस्लिम और धर्म के नाम पर बंटकर देश में राज करना

चाहती है। मोदी ने अमेरिका के इस कु—त्य के खिलाफ ना बोलकर देश को अपमानित करने का काम किया है। जिसे देश की जनता बर्दास्त नहीं करेगी और कांग्रेस पूरे राज्य में इसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगी। पूर्व पार्षद नूनू सहगल ने कहा कि जो लोग वापस भेजे गये उनमें कई गुजराती थे। तो क्या यह समझा जाय कि गुजरात मश्रडल की बात करने वाली मोदी सरकार गुजरात के युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका का रूख करना पड़ा।

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ओमप्रकाश सती ने कहा कि अपनी जमीनें गहने और घर बेचकर एक बेहतर जीवन की तलाश में हजारों भारतीय नागरिक अमेरिका गये, क्योंकि दो करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने की बात करने वाली मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीठ दिखाकर भाग गई। चन्दन सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती के बड़े-बड़े दावे किये गए थे, लेकिन फिर भी यह अपमानजनक घटना क्यों? गोष्ठी का संचालन प्रदेश महामंत्री मानवेन्द्र सिंह ने किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजय प्रताप मल्ल ने कहा कि मोदी ने देश को अपमानित करने का काम किया है जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। गोष्ठी में महिपाल शाह, आशीष उनियाल, अनिल नेगी, अजय सूद, शरीफ बेग, सिद्धार्थ पोखरियाल, प्रदेश प्रवक्ता सुलेमान अली, रिपूदमन सिंह, अरून बलूनी, संजय थापा, बब्लू खुराना, पारितोष सिंह, करन घाघट, मुकेश सोनकर, विनीत सिंह आदि उपस्थित थे।

निकाय चुनाव बाद कांग्रेस में सिर फुटव्वल चिंताजनक : चौहान

सार्वजनिक मंच पर लग रहे आरोप-प्रत्यारोप निराशाजनक: भाजपा

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में मचे सिरफुटव्वल में टिकट बेचने, दलाली जैसे आरोपों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद चिंताजनक बताया है। कांग्रेस के ऐसे कृत्यों से राजनैतिक दलों और उनकी कार्य संस्कृति की खराब छवि बन रही है। चौहान ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मसला बताया, लेकिन उनके अंदरूनी हालातों को दुर्भाग्यपूर्ण और समाज के लिए भी हानिकारक करार दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेसी महाभारत पर चुटकी लेते हुए कहा कि हालांकि एक नजर में यह उनके घर का मामला है, लेकिन जिस तरह सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं, वह निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के बाद आज उनकी पाटह के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री टिकटों को बेचने और दलालों की पाटह बनने का सनसनी आरोप लगा रहे हैं। और यह सब बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले मंच पर दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर बंद कमरों के अंदर हुई बैठक

के हालात तो और भी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। वहीं इससे पूर्व भी टिकट वितरण के दौरान देहरादून में घपलेबाजी और पैसों की लेनदेन के आरोपों को भी लोगों ने मीडिया में देखा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, एक तरफ कांग्रेस अपने को देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पाटह बताती है, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता कार्यकर्ता इस तरह के आपत्तिजनक खुलासे करते हैं। कोई चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाता है, कोई दलालों को पाटह में निर्णायक बनाने का खुलासा करता है। प्रदेश अध्यक्ष पाटह में विरोधी दलों के स्लीपिंग सेल होने और जयचंदों की भरमार की बात कई मर्तबा स्वीकार कर चुके हैं। इसी तरह के अनेक गंभीर आरोप लगना, अब कांग्रेस पाटह में आम हो गया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों और अनैतिक प्रक्रिया से कांग्रेस अपने साथ राजनैतिक संस्कृति को भी खराब कर रही है। इस तरह की घटनाक्रम, राजनीतिक दलों और लोकतंत्र की छवि के लिए भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन, विकास और लोकतंत्र विरोधी होने के साथ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी घातक साबित हो रही है।

मैदान के भीतर ही नहीं बाहर भी पसीना बहा रही हैं बेटियां

राष्ट्रीय खेलों की अहम व्यवस्थाओं को संभाल रही 1053 महिला वॉलंटियर

देहरादून। राष्ट्रीय खेलों में मैदान के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी बेटियां जमकर पसीना बहा रही हैं। अपने जुझारूपन का सुबूत दे रही हैं। यह बेटियां वो हैं, जिन्हें राष्ट्रीय खेलों की अहम व्यवस्थाओं में वॉलंटियर बतौर तैनात किया गया है। पूरे प्रदेश में ऐसी 1053 महिला वॉलंटियरों को ड्यूटी पर लगाया गया है। उत्तराखंड में पहली बार कोई ऐसा आयोजन हो रहा है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिला वॉलंटियरों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।

उत्तराखंड में 38 वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खेल के अलावा तमाम अन्य क्षेत्रों में भी देश दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। एक हजार से ज्यादा महिला वॉलंटियरों का राष्ट्रीय खेलों से सीधे जुड़ाव महिला सशक्तिकरण की सुंदर तस्वीर बना रहा है। वॉलंटियर बनने के लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने तीस हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए थे। प्रारंभिक परीक्षा और प्रशिक्षण के बाद पूरे प्रदेश में 2451 वॉलंटियरों को व्यवस्थाओं से जोड़ा गया। इनमें से पुरुष वॉलंटियरों की संख्या 1398 है। कुल तैनात वॉलंटियरों में पुरुष वॉलंटियर 57.4 प्रतिशत हैं, जबकि 42.96 प्रतिशत महिला वॉलंटियर ड्यूटी कर रही हैं। यह सारे वॉलंटियर सामान्य हैं, जिन्हें पार्किंग, खिलाड़ियों को लाने-ले जाने, मेडल सेरमेनी के दौरान सहयोग करने जैसे कार्यों में लगाया गया है। इनके अलावा, नेशनल फेडरेशन स्पोर्ट्स अथ्रफ इंडिया से संब) विशिष्ट वॉलंटियर भी अपना अलग से योगदान कर रहे हैं। उनकी खेल पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें खेल गतिविधियों से सीधे जोड़ा गया है। कोटद्वार की रहने वाली मानसी दून विश्वविद्यालय से मीडिया एंड मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। वह वॉलीबाल की खिलाड़ी भी हैं। वह कहती हैं-बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं। मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। वॉलंटियर बतौर राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनी हूँ, यह बड़ी बात है। देहरादून की रहने वाली रिदिमा का भी यही कहना है। वह कहती हैं-इतने बड़े आयोजन से जुड़कर एक्सपोजर मिलता है। इसके अलावा, अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वह दूसरे मैच भी देख पा रही हैं। रिदिमा बॉस्केटबॉल खेलती हैं। गौचर-चमोली की रहने वाली स्नेहा आर्या कहती हैं-राष्ट्रीय खेलों के बड़े आयोजन में जुड़ना गौरवान्वित करने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों में हम बेटियों के जज्बे और हौसले को लगातार देख रहे हैं। विभिन्न खेलों में बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और मेडल जीते हैं। खेलने के अलावा इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में बेटियां अपनी अपनी भूमिकाओं में सक्रिय योगदान कर रही हैं। तमाम व्यवस्थाओं में वह कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं, यह सराहनीय है।

अब 65 की उम्र पूरी होने पर रिटायर होंगे विशेषज्ञ चिकित्सक

देहरादून। प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को नये साल का तोहफा दिया है। सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ डाक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। स्वास्थ्य सचिव डा. आर. राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि आयु सीमा बढ़ाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टरों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को पांच साल की सेवावृत्ति देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य सचिव डा. आर. राजेश कुमार के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा, एवं उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी।

सीएम ने साइकिलिंग पदक विजेताओं को पहनाए मेडल

सम्मानित कर किया उत्साहवर्धन, साइकिल भी चलाई

रुद्रपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल में स्पोर्ट्स स्टेडियम वैलोड्रोम में साइकिलिंग पदक विजेताओं को मेडल पहना कर सम्मानित किया व शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री धामी ने बीती गुरुवार को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के अन्तर्गत शिवालिक वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता को दर्शक दीर्घा से देखा। उन्होने वेलोड्रोम पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर ट्रैक पर साइकिलिंग भी की।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुरुष वर्ग के टीम परस्यूट डिस्टेंस 4000 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, रजत पदक विजेता पंजाब व कांस्य पदक विजेता राजस्थान को मैडल व पहाड़ी टोपी पहनाकर सम्मानित किया व उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ भोजन किया व खिलाड़ियों के लिए किये गए व्यवस्थाओं के बारे में खिलाड़ियों से जानकारी ली जिस पर खिलाड़ियों ने



सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का देहरादून से शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि खेल के शुभारम्भ होने के दिन से ही पूरे प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताओं के संचालन हेतु लगभग 20 हजार लोगों द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे पूरे प्रदेश के लिए अत्यन्त गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं पूरे प्रदेश में हो विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहे विभिन्न प्रतियोगिताओं में जा कर खिलाड़ियों से मिल रहा हूँ और व्यवस्थाओं को देख रहा

हूँ। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहतर देखने को मिल रहा है, अभी तक लगभग 30 से अधिक मेडल उत्तरखण्ड के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा, उनके कहे हुए शब्द सिंगी की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वेलोड्रोम अद्भुत है जिसकी सराहना देश-विदेश से आने वाले खिलाड़ी भी

कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर बहुउद्देशीय हाल का भी निर्माण किया गया है, खटीमा के चकरपुर में भी मलखम्ब, टनकपुर में राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित होनी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 11 विभिन्न स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, जो अपने आप में बहुत शानदार आयोजन हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिताएं निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं/खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी और सभी खेल के क्षेत्र में अपना शानदार भविष्य बनायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस राष्ट्रीय खेल का शुभारम्भ हुआ था और 14 फरवरी को हल्द्वानी में गृहमंत्री अमित शाह इसका समापन

करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 46वीं वाहिनी पीएसी में पहुंचकर शश्वटगन और स्कीट प्रतियोगिता का विधिवत फीता काटकर व पूजा अर्चना कर खेल शुभारम्भ की घोषणा की। उन्होंने शॉटगन से टैप शूटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मिलकर अग्रिम शुभकामनाएँ दीं। इस दौरान विधायक शिव अरोरा, दर्जामंत्री अनिल कपूर डब्लू उत्तम दत्ता, नवनिर्वाचित मेयर विकास शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिन्दल, जिला महामंत्री अमित नारंग, पूर्व मेयर रामपाल सिंह, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, निदेशक खेल प्रशान्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकान्त मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी, सीओ निहारिका तोमर, नगर आयुक्त नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत, पूर्व महाचिव राष्ट्रीय ओलम्पिक ऐशोसिएशन राजीव मेहता, अध्यक्ष राज्य ओलम्पिक ऐशोसिएशन महेश नेगी, जिला क्रीडा अधिकारी जानकी कार्की, महासचिव साइकिलिंग एसोसिएशन देवेश पाण्डे, साइकिलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी, खिलाड़ी मौजूद थे।

बीआरपी-सीआरपी भर्ती में देरी पर विभागीय मंत्री नाराज

उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के बाद अधिकारियों को दिये शीघ्र भतह के निर्देश

देहरादून। समग्र शिक्षा के अंतर्गत लम्बे समय से लटकी सीआरपी- बीआरपी भर्ती पर विभागीय मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुये भर्ती प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रयाग पोर्टल में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों का शीघ्र निस्तारण कराये ताकि शीघ्र भतह प्रक्रिया शुरू की जा सके।

विद्यालयी शिक्षा विभाग में शैक्षणिक गतिविधियों के सुधार के लिये समग्र शिक्षा के तहत ब्लश्वक स्तर पर ब्लश्वक रिसोर्स पर्सन डब्ल्यूबीआरपीऋ के कुल 285 पदों तथा संकुल स्तर पर संकुल रिसोर्स पर्सन डब्ल्यूसीआरपीऋ के 670 रिक्त पदों पर कार्मिकों की तैनाती न होने पर शिक्षा मंत्री ड.धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताते हुये लम्बित प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने विगत सोमवार को



सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक का हवाला देते हुये बताया कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से सीआरपी-बीआरपी के कुल 955 रिक्त पदों पर भतह प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रयाग पोर्टल की आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर स्वयं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग संबंधित शासनादेश में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा ताकि पोर्टल के माध्यम से होने वाली सभी आउटसोर्स भतह में आ रही व्यवहारिक अड़चनों को दूर किया जा सके।

डा. रावत ने बताया कि प्रयाग पोर्टल पर प्रदेश के हजारों छात्र-छात्राओं ने सीआरपी- बीआरपी के लिये अपना पंजीकरण कराया है, पोर्टल की विसंगतियां दूर होते ही एक माह के भीतर

सीआरपी- बीआरपी के रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से युवाओं को मेरिट के आधार पर तैनाती दी जायेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके लिये अन्य सभी तैयारियां पुख्ता रखने के निर्देश दे दिये हैं। डा. रावत ने बताया कि बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति से विद्यालयों में अनुश्रवण कार्यों में तेजी आयेगी साथ ही बीआरपी-सीआरपी की जिम्मेदारी से सैकड़ों शिक्षकों को भी मुक्त किया जा सकेगा, जिससे विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

पोर्टल की स्वामियों के चलते अटकी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती

विभागीय मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा विभाग में लगभग 2500 चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं। जिनको प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरे जाने की अनुमति राज्य कैबिनेट द्वारा मिल चुकी है। लेकिन प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भतह प्रक्रिया में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों के चलते भतह नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि प्रयाग पोर्टल की खामियां दूर होते ही विभाग में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भतह शुरू कर दी जायेगी।

यूसीसी:महिलाओं और बच्चों को मिली सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा



देहरादून। समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट तय करने वाली विशेषज्ञ कमेटी की सदस्य और दून विश्वविद्यालय की वीसी प्रो. सुरेखा डंगवाल के मुताबिक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के जरिए ना सिर्फ महिलाओं और बच्चों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई है। बल्कि इससे विवाह संस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रो. सुरेखा डंगवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की भावना ही, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करते हुए समता स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जिसमें महिलाओं को पता ही नहीं होता था कि उनके पति की दूसरी शादी भी है। कुछ जगह धार्मिक परंपराओं की आड़ में भी ऐसा किया जा रहा था। इस तरह अब शादी का पंजीकरण अनिवार्य किए जाने से, महिलाओं के साथ इस तरह का धोखे की सम्भावना न्यूनतम हो जाएगी। साथ ही इससे चोरी छिपे 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी की कुप्रथाओं पर रोक लग सकेगी। इससे बेटियां निश्चित होकर अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकती हैं।

प्रो.सुरेखा डंगवाल के मुताबिक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में व्यक्ति की मौत होने पर उनकी सम्पत्ति में पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता को भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं। इससे बुजुर्ग माता पिता के अधिकार भी सुरक्षित रह सकेंगे। इसी तरह लिव इन से पैदा बच्चे को भी विवाह से पैदा संतान की तरह माता और पिता की अर्जित सम्पत्ति में हक दिया गया है। इससे लिव इन रिलेशनशिप में जिम्मेदारी का भाव आएगा, साथ ही विवाह एक संस्था के रूप में और अधिक समृद्ध होगा साथ ही स्पष्ट गाइडलाइन होने से कोर्ट केस में भी कमी आएगी।

प्रो. सुरेखा डंगवाल ने कहा भारत का संविधान दो वयस्क नागरिकों को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने की अनुमति देता है। इसके लिए पहले से ही विशेष विवाह अधिनियम मौजूद है, इसमें भी आपत्तियां मांगी जाती हैं। अब इसी तरह कुछ मामलों में अभिभावकों को सूचना दी जाएगी। वहीं लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही धर्मांतरण कानून लागू है